

सम्पादकीय

मसलों पर समय सीमा तय करने पर विवाद क्यों ?

उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के स्तर पर विधेयक स्वीकृत करने संबंधी समय सीमा निर्धारित क्या की, समूचे राजनीतिक जगत में जैसे भूचाल आ गया। नेताओं द्वारा इसे विधायिका की कार्यवाही में सीधा हस्तक्षेप मानते हुए इस कार्यवाही को न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमा लांघने जैसे बयान दिए जाने लगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान दे डाला कि संविधान की मूल भावना के 'अंतिम स्वामी' चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और संसद से ऊपर कोई भी नहीं है। भजपा संसद निशिकांत दुबे तो इतने आगे चले गए कि, यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, और भारत में युद्ध युद्ध के लिए सीजेआई खन्ना जिम्मेदार हैं धनखड़ के बयान पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ कानूनविद कपिल सिंबल मैदान में आए। उन्होंने कहा कि न तो संसद और कार्यपालिका नहीं संविधान सर्वोच्च है जिसके प्रावधानों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह समझा है। सिंबल ने उपराष्ट्रपति का नाम तो नहीं लिय मगर कहा कि शीर्ष अदालत के हालिया फैसले, जिनकी कुछ भाजपा नेताओं और उपराष्ट्रपति ने आलोचना की है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप और राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं। संसद को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है मगर संविधान की व्याख्या करना और पूर्ण न्याय करना न्यायालय का दायित्व है। जहां तक निशिकांत दुबे का प्रश्न है भाजपा ने उनके बयानों से खुद को अलग कर लिया है लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका और विधायिका के बीच ऐसी परिस्थितियां निस्पंदेह दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मगर यह भी तय है कि किसी भी समूद्र लोकतंत्र में जनहित से जुड़े कार्यों को लेकर समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। तमिलनाडु के राज्यपाल के रविं के मामले को देखें तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पारित अनेक विधेयक तो तीन साल से ज्यादा की अवधि के बाद भी उनके कार्यालय में लॉबिट थे। और यह अकेला मामला नहीं है। विरोधी पक्ष की सरकारें बाले देश के कितने ही राज्यों में विधियों को अधिकारी आवाज उठाती हैं। संवैधानिक रूप से राज्यपाल पद बेहत मर्यादित है और उस पर बिना किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रह के विशुद्ध रूप से राज्य सरकार की प्रशासनिक मदद का दायित्व है।

टकराव की यह परिस्थितियां और राज्यपाल पद का राजनीतिक दुरुपयोग पहले भी होता रहा है और पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों ने तो चुनी हुई राज्य सरकार गिराने तक में इसका प्रयोग किया है। जहां तक विधायिका का प्रश्न है, संसद की कार्यवाही कमोबेश हर सत्र में होना और बहिष्कार का शिकार होती दिखती है। स्वस्थ बहस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह संस्था अब सरकार और विरोध पक्ष के संघर्ष के लिए ज्यादा पहचानी जाती है। जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक सालों से लॉबिट पड़े हैं। सदस्यों के लॉबिट प्राइवेट विधेयकों की संख्या तो सैकड़ों पार कर रही है। यही हाल विधानसभाओं का है। महत्वपूर्ण विधेयक लॉबिट रहते हैं और जो स्वीकृत हो जाते हैं वे राजनीतिक रस्साकपी का शिकार होकर वर्षों राज्यपाल के स्तर पर धूल फांकते रहते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए प्रश्न या समस्या पर मंत्री की घोषणा आशासन बन जाती है। सत्र में पूछे गए प्रश्न के उत्तर के आधार पर भी आशासन बन जाते हैं। ऐसा आशासन निभाना संवैधानिक बाध्यता न सही नैतिक आवश्यकता तो है। यह चुनाव मंच पर किया गया वादा नहीं अपितु सदन जैसे संवैधानिक मंदिर में दिया गया भरोसा है। मगर इसके प्रति आवश्यक गंभीरता का सर्वथा अभाव है। मध्यप्रदेश विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में ही ऐसे दाई हजार के लगभग लॉबिट आशासन बताते हैं कि विधानसभा में किसी जनोपयोगी आवाज उठ भी जाए तो उसकी सुनवाई जरूरी नहीं है। क्या ऐसे आशासनों की पूर्ति के लिए समय-सीमा निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है? यह लेट लॉबिटों की सिफर संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही तक ही सीमित नहीं है। निवाचित सरकारें जन सामान्य के हितों और शिकायतों से संबंधित कार्यों के समय-सीमा निर्धारित कर ही अपना दायित्व पूरा समझ लेती हैं। प्रदेश को ही लें, आम जनता की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए बनाई गई सीएम हेल्पलाइन में पिछले अक्टूबर की स्थिति में 7 लाख से अधिक शिकायतें पेंडिंग थीं, जिनमें से 3 लाख से अधिक 100 दिनों की समय सीमा पार कर चुकी थीं। इनमें पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में राशि न मिलने, पीएम मारु वंदन योजना, श्रमिक प्रसूति सहायता और जननी सूरक्षा, पुलिस विवेचना में लापरवाही और कार्ट में केस पेंडेंसी और संबल योजना का लाभ न मिलने जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। तथाकथित निराकृत प्रकरणों में भी शिकायतें येन-केन प्रकारे निपटाएं जाने जैसे मामते ही ज्यादा थे। सरकारों को समझना चाहिए कि उनका दायित्व सिफर जनोपयोगी योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं है। अफसरसहाई इन लाभों को जन-सामान्य तक पहुंचाने का जरिया है और आग यह व्यवस्था थीक काम नहीं करती और लाभ निर्दिष्ट व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है तो सारा का सारा तामग्नाम व्यर्थ है। हर कार्य के लिए न सिफर समय-सीमा निर्धारित होना चाहिए और लॉबिट उसका काम नहीं होता है तो फिर इसे सीमा का उच्चतम व्यायालय हस्तक्षेप करता है तो फिर इसे सीमा का उल्लंघन कराया उचित नहीं होगा तो विधायिका की कार्यवाही को न्यायपालिका द्वारा अपनी सीमा लांघने पर विवाद कैसे हो सकता है।

आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिशोध एवं शौर्य का प्रतीक है आप्रेशन सिन्दूर

- योगेश कुमार गोयल
- आतंक के गढ़ में भारत का निर्णयक प्रहर
भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में धूसंपैठ, आमन्त्राती हमले और में हुए आतंकी हमले का जवाब दे रहे थे। बहावलपुर-जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ में वह ही जाता दिया है कि अब वह न तो चुप रहेगा और न ही आतंकी हमलों को बर्दाशत करेगा। इसे संघर्ष के लिए जाने गई थी और यह हमला नैतिक बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, और भारत में युद्ध युद्ध के लिए सीजेआई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए लांच पैड के रूप में काम आते हैं।

ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अप्रेशन के केवल उन आतंकी द्वारा हमलों के विरुद्ध था, जो लगातार भारत में धूसंपैठ, आमन्त्राती हमले और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए थे। बहावलपुर-जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ में वह ही जाता दिया है कि अब वह न तो चुप रहेगा और न ही आतंकी हमलों को बर्दाशत करेगा। इसे संघर्ष के लिए जाने गई थी और यह हमला नैतिक बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, और भारत में युद्ध युद्ध के लिए सीजेआई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए लांच पैड के रूप में काम आते हैं।

ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अप्रेशन के केवल उन आतंकी द्वारा हमलों के विरुद्ध था, जो लगातार भारत में धूसंपैठ, आमन्त्राती हमले और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए थे। बहावलपुर-जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ में वह ही जाता दिया है कि अब वह न तो चुप रहेगा और न ही आतंकी हमलों को बर्दाशत करेगा। इसे संघर्ष के लिए जाने गई थी और यह हमला नैतिक बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, और भारत में युद्ध युद्ध के लिए सीजेआई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए लांच पैड के रूप में काम आते हैं।

ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अप्रेशन के केवल उन आतंकी द्वारा हमलों के विरुद्ध था, जो लगातार भारत में धूसंपैठ, आमन्त्राती हमले और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए थे। बहावलपुर-जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ में वह ही जाता दिया है कि अब वह न तो चुप रहेगा और न ही आतंकी हमलों को बर्दाशत करेगा। इसे संघर्ष के लिए जाने गई थी और यह हमला नैतिक बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, और भारत में युद्ध युद्ध के लिए सीजेआई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए लांच पैड के रूप में काम आते हैं।

ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अप्रेशन के केवल उन आतंकी द्वारा हमलों के विरुद्ध था, जो लगातार भारत में धूसंपैठ, आमन्त्राती हमले और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए थे। बहावलपुर-जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ में वह ही जाता दिया है कि अब वह न तो चुप रहेगा और न ही आतंकी हमलों को बर्दाशत करेगा। इसे संघर्ष के लिए जाने गई थी और यह हमला नैतिक बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, और भारत में युद्ध युद्ध के लिए सीजेआई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए लांच पैड के रूप में काम आते हैं।

ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अप्रेशन के केवल उन आतंकी द्वारा हमलों के विरुद्ध था, जो लगातार भारत में धूसंपैठ, आमन्त्राती हमले और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए थे। बहावलपुर-जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ में वह ही जाता दिया है कि अब वह न तो चुप रहेगा और न ही आतंकी हमलों को बर्दाशत करेगा। इसे संघर्ष के लिए जाने गई थी और यह हमला नैतिक बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, और भारत में युद्ध युद्ध के लिए सीजेआई और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लिए लांच पैड के रूप में काम आते हैं।

ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अप्रेशन के केवल उन आतंकी द्वारा हमलों के विरुद्ध था, जो लगातार भारत में धूसंपैठ, आमन्त्राती हमले और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए थे। बहावलपुर-जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ में वह ही जाता दिया है कि अब वह न तो चुप रहेगा और न ही आतंकी हमलो

क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की मांग आज भी

सूचना तकनीक के इस दौर में क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यवसायों तक को होती है। यह पेशेवरों क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और सेवाओं को डिजाइन करने और अच्छे से प्रबंधित करना आता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यवसायों



तक को होती है। यह पेशेवरों प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए और वास्तविक दुनिया के मार्केटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और डिजाइन किया गया है, जिसका परिदृश्यों में जेमिनी मॉडल लागू सेवाओं को डिजाइन करने और अच्छे से प्रबंधित करना आता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग में कुशल पेशेवरों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टार्टअप से लेकर बड़े व्यवसायों

तक को होती है। यह पेशेवरों प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए और वास्तविक दुनिया के मार्केटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम और डिजाइन किया गया है, जिसका परिदृश्यों में जेमिनी मॉडल लागू सेवाओं को डिजाइन करने और अंतिम लक्ष्य क्लाउड और ऑन-करने के विभिन्न तरीकों के बारे में अच्छे से प्रबंधित करना आता है। प्रिमाइसेस डेटा को कोनेट और सिखाया जाता है।

यही बजह है कि इन पेशेवरों की साझा करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग जेन एआई एप विथ जेमिनी और मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में को मूल रूप से एक डिलीवरी स्ट्रीमलिट - जेन एआई एप विथ अगर आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग पद्धति के रूप में सोचें। ऐसे प्रकार जेमिनी और स्ट्रीमलिट आपको में बेहतर करियर बना सकते हैं। से यह डेटा स्टोरेज भी है।

इसमें कौशल बढ़ाने के लिए आप इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंगेज मॉडल और जेमिनी एपीआई के साथ पद्धाई के साथ-साथ विभिन्न - शुरुआती स्तर पर यह माइक्रो-क्लाउड आधारित कोर्स कर सकते लर्निंग कोर्सों को आपको लार्ज लैंगेज रन के साथ स्ट्रीमलिट एप्लिकेशन हैं। इन कोर्सों को करने से आपको मॉडल की ओटी-ओटी बारीकियों बनाने का तरीका सीखाएगा।

जेमिनी, जेनरेटिव एआई को के बारे में बताएगा। इस कोर्स में इमेज जेनरेशन - पिछले कुछ सालों में अनुसंधान और स्ट्रीमलिट के साथ एलएलएम के उपयोग और इसके एप्लीकेशन बनाने का मौका प्रदर्शन को अच्छा बनाने के लिए एपीआई के साथ पद्धाई के साथ-साथ संग्रहीत और एक्सेस करने का शामिल किए गए हैं। जिनकी मदद जोड़कर सीखें से कौशल निखरें।

एक तरीका है जो आपके कंप्यूटर से आप खुद का जेनरेटिव एप बना सकते हैं। इसके बाद याद रखें कि उपयोग करता है। संखेप में, प्रॉम्प्ट डिजाइन इन वर्टेक्स एआई अटरपुट क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स में जेनरेटिव एआई अटरपुट और बीटेक का अंतर

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं के लिए बीई और बीटेक का अंतर जानना जरूरी है। तभी वे अंदाज लगा सकेंगे कि कौन सा कोर्स उनके करियर के लिए अच्छा रहेगा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई एक पारंपरिक डिग्री कोर्स है, जो कि इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल और बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को घोरी बेस्ट नॉलेज अधिक दी जाती है। जिससे कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ सकें। वहीं इस कोर्स में प्रैक्टिकल और लैंब वर्क भी होते हैं। लेकिन इस कोर्स की घोरी की गहराई अपेक्षाकृत अधिक होती है। बीई और बीटेक दोनों ही डिप्लियां इंजीनियरिंग की फील्ड में समान मान्यता प्राप्त है। इन दोनों कोर्स में फर्क सिर्फ करियर गोल्स और पढ़ाई के तरीके में होता है। ऐसे में सही कोर्स का चुनाव करके आपके लक्ष्य, राच और पढ़ाई के प्रति रुख पर निर्भर करता है।

बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी

यह कार्स प्रैक्टिकल और एप्लिकेशन-ऑपरेटर डिग्री है। इसमें तकनीकी पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस कोर्स में इंडस्ट्री में चलने वाले ट्रेन्स, नई टेक्नोलॉजी और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आदि पर फोकस किया जाता है। इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार बीटेक कोर्स डिजाइन किया जाता है। जिससे कि स्टूडेंट्स सीधे तौर पर जॉब के लिए तैयार हो सकें।

बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स घोरी और फंडामेंटल्स पर अधिक केंद्रित होता है। वहीं बीटेक में इंडस्ट्री स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान दिया जाता है।

बीई कोर्स में एकेडमिक और रिसर्च बेस्ड स्टडी अधिक की जाती है।

जबकि बीटेक में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट वर्क पर अधिक फोकस होता है।

बीई का सिलेबस थोड़ा ट्रेडिशनल होता है और बीटेक का सिलेबस इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से बार-बार अपडेट होता रहता है।

कैसे चयन करें

अगर आपका रुझान इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को गहराई से समझने में और पूर्वाचार में रिसर्च या फिर हायर एज्युकेशन किए जाने में हैं, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स आपके लिए बेहतर ऑफशोर साबित हो सकता है।

वहीं आगर आप पढ़ाई के फौरन बाद किसी टेक्निकल जॉब में जाना चाहते हैं इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर बीटेक कोर्स आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा।

योग्यता - आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल, सिविल या

सहायक अभियंता के पदों पर 28 मई तक कर सकते हैं आवेदन

सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए अच्छी मौका है। बिहार राज्य के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के पदों पर वैकेंसी निकली है। ऐसे में आप 28 मई तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बिहार राज्य के विभिन्न विभागों में साल होनी चाहिए। वहीं आयु सहायक अभियंता (असैनिक, यांत्रिक, विद्युत) के पदों पर की भर्ती निकली है।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए अच्छी मौका है। बिहार राज्य के विभिन्न विभागों में होनी चाहिए। बिहार लोक सेवा आयोग-आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। वहीं आयु सीमा-आवेदन के इच्छुक सहायक अभियंता (असैनिक, यांत्रिक, विद्युत) के पदों पर की भर्ती निकली है।

की कूल संख्या 1024 है। बता दें कि भर्ती उन उम्मीदवारों के एक सुनहरा मौका है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश में होनी चाहिए।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिप्लिया 1024 है। बता दें कि भर्ती उन उम्मीदवारों के एक सुनहरा मौका है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश में होनी चाहिए।

गणना 01 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के कैर्डिडेट्स को आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आवेदन शुल्क-सामान्य उम्मीदवारों की फीस - 750 रुपए

जाकर आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन की दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना होगा।

पद - कुल 1024 असहायक अभियंता पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिनमें से सहायक अभियंता 984 पद हैं, जिनमें से 324 पद महिला के लिए हैं। वहीं 36 सहायक अभियंता (यांत्रिक) 36 पद हैं। जिनमें से 8 पद महिला के लिए शामिल हैं। वहीं सहायक अभियंता (विद्युत) के 4 पद हैं।

योग्यता - आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल, सिविल या

एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय से अधिक अवधारणा में आवेदन करना हो सकता है।

एजुकेशन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों में आवेदन करना हो सकता है। इन सबके अतिरिक्त फिल्म इंडस्ट्री, चर्च म्यूजिशियन नॉटर्ड एंड डिस्ट्री, नॉटर्ड एंड डिस्ट्री, कॉर्स शो, रॉक और जैजुप्र इत्यादि में भी इनकी भूमिका अरेंजिंग, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, प्रोडेक्शन, एकेडमिक और अन्य विद्यालयों में आवेदन करना हो सकता है।

एजुकेशन के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की फीस - 200 रुपए

बिहार के स्थायी निवासी सभी आरक्षित वर्ग के लिए शामिल हैं। वहीं सहायक अभियंता (विद्युत) के 4 पद हैं।

योग्यता - आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल, सिविल या

एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय से अधिक अवधारणा में आवेदन करना हो सकता है।

एर्डाइआर के अनुसार "ऐसा मानना है कि इस सुविधा के शुरू होने से आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहुंच और सुविधा के रूप में संगीत के अंडिशन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालयों में आवेदन करना हो सकता है।"

यहाँ आयोजित हुए

